साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 24 फरवरी- 2 मार्च 2025 वर्ष-10, अंक-45

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

### मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में की बड़ी घोषणा

# धान उत्पादक किसानों को 2000 रु. प्रति हेक्टेयर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से उनके बैंक खाते में अंतरित करेगी। इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने पहले कोदो-कुटकी के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। गेहूं उत्पादक किसानों से भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल उपज खरीदी जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों से सरकार दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। किसानों को सोलर पंप देकर उन्हें बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलाई जायेगी।

अब 250 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बनाई जाएंगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया है कि अब 250 की आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बनाई जाएंगी। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में आनंद होना चाहिए। यह प्रदेश सरकार का संकल्प है। गरीबों का भी देश-प्रदेश में अधिकार है। समाज के वंचित वर्ग को पक्के मकान मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली और पानी है। यहां कोई भी उद्योग फल-फूल सकता है। सरकार ने ऐसी नीतियों को मंजूरी दी है कि स्थानीय युवा भी उद्योगपति बनें और खुद कमाने के साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। सरकार ने दो से ढाई करोड़ की फैक्ट्री लगाने पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया है।

## मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

- उमरिया जिले के ग्राम पौड़ी में 600 मेगावॉट की ताप विद्युत परियोजना की इकाई स्थापित की जाएगी।
- बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू का निर्माण किया जाएगा। यह इलाका भविष्य की दृष्टि से पर्यटन केंद्र बनेगा।
- बिलासपुर में कॉलेज निर्माण और भगवान विष्णु के धाम टकटई को 4 स्थानों से जोड़कर पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा।
- उमरिया में हॉकी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एस्ट्रो टर्फ बनेगी।

## प्रदेश के सिंचाई रकबे को एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने गतिविधियां की जाए पूर्णः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे को वर्ष 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। अतः सभी परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों का संचालन समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बैठक में दिए। समत्व भवन में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत टेरिया नाला बांध, सानेर बांध और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य, सोण्डवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, धार उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, बहोरीबंद उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, ढ़ीमरखेड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण, महेश्वर-जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ओंकारेश्वर और नावघाट-खेड़ी जिला खण्डवा में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण और इंदिरा सागर ओंकारेश्वर पम्प स्टोरेज परियोजना पर भी चर्चा हुई।

### दरभंगा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पर मखाना किसान संवाद में शामिल हुए

# तालाब में उतरे कृषि मंत्री शिवराज समझी मखाना खेती की प्रक्रिया

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा में तालाब में उतरकर मखाना उत्पादक किसानों से सीधी चर्चा की। उन्होंने मखाने की खेती की पूरी प्रक्रिया समझी और मखाना उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को जानने के साथ ही किसानों से सुझाव भी लिए। शिवराज सिंह ने कहा कि मखाना की खेती कठिन है और तालाब में दिनभर रहकर खेती करनी होती है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है और इस बोर्ड के गठन के पहले वे किसानों से सुझाव लेकर चर्चा कर रहे हैं, ताकि किसानों की वास्तविक समस्याएं समझी जा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर संवाद कार्यक्रम में मखाना के किसानों से सुझाव लेने के साथ ही उन्हें संबोधित भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम केवल विभाग नहीं चलाते हैं, बल्कि गहराई तक जाकर, कैसे हम किसानों की तकलीफदूर करें, इसकी कोशिश करते हैं।

## कांटा रहित मखाने का विकसित करने के दिए निर्देश

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि सही अर्थों में आपसे समझकर कि मखाना बोर्ड बने तो कैसे बने, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है आईसीएआर व अनुसंधान केंद्र कांटा रहित मखाने का बीज विकसित करने पर काम करें। ये असंभव नहीं है, यहाँ बात मैकेनाइजेशन की आई, पानी में डुबकी लगाकर निकालना पड़ता है। पूरे डूब गये आँख, नाक, कान में पानी और केवल पानी ही नहीं होता है, पानी के साथ कीचड़ भी होता है। अब आज के युग में मैकेनाइजेशन से ये चीज बदली जा सकती है, अभी यंत्र तो बने हैं, लेकिन उसमें आधा मखाना आता है और आधा आता ही नहीं है। गुरिया बड़ी मुश्किल से निकलती है और इसलिए मैकेनाइजेशन होगा और ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो गुरिया को आसानी से बाहर खींच लाए।

### मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य 25 फरवरी को होगा सहकारिता अनुबंध

# दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आगामी 25 फरवरी को एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहकार्यता अनुबंध (कोलैबोरेशन एग्रीमेंट) का निष्पादन किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की यह बड़ी उपलब्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रि-परिषद द्वारा एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य होने वाले सहकारिता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दे दी गयी है। अब यह अनुबंध निस्पादत किया जा रहा है। इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जायेगी। इन सबके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र-2023 में प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर खोले जाने और श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत ढाई हजार करोड़ के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख है। इन संकल्पों को पूरा करने में यह अनुबंध महत्वपूर्ण साबित होगा। यह राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को मजबूत करेगा।

## प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में दुग्ध कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा। एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है, 9 हजार दुग्ध समितियां के माध्यम से लगभग 18 हजार ग्रामों को कवर किया जा सकेगा। दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी द्वारा दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) के माध्यम से कवर किए गए गांवों को 1390 से बढ़ाकर 2590 किया जाएगा तथा दूध की खरीद को 1.3 लाख किलोग्राम से बढ़कर 3.7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

### तीन दिन की गिनती में सामने आए आंकड़े, प्रदेश में 7 प्रजाति, वन विहार में सफेद पीठ वाले गिद्ध

# 10 साल में दोगुनी हो गई प्रदेश में गिद्धों की संख्या, पन्ना नेशनल पार्क में 900 से ज्यादा

## टाइगर-चीता स्टेट मप्र में गिद्धों की संख्या 12000 पार, आवास पर बठे गिद्धों को ही गिना

जागत गांव हमार, भोपाल

टाइगर, चीता और तेंदुआ स्टेट मध्यप्रदेश में गिद्धों की संख्या 12 हजार से ज्यादा हो गई है। 3 दिन हुई गिनती में ये आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में 10 साल के अंदर गिद्धों की संख्या दोगुनी हुई है। अभी कुल 7 प्रजातियां पाई गई। इनमें भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध भी शामिल हैं। बता दें कि 17, 18 और 19 फरवरी को वन विभाग के 16 सर्कल , 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों की गिनती की गई थी। जिसके आंकड़े अब सामने आए हैं। इसके मुताबिक, प्रदेश में अभी 12 हजार 981 गिद्ध हैं।

**ये खास तौर पर ध्यान रखा:** गिद्धों की गणना में घोंसलों के आसपास बैठे गिद्धों एवं उनके नवजातों की गिनती के दौरान कई बातों का ध्यान रखा गया। केवल आवास स्थलों पर बैठे हुए गिद्धों को ही गिना गया। डेटा संकलन का कार्य वन विहार में हुआ।

**ऐसे बढ़ती गई गिद्धों की संख्या:** प्रदेश में गिद्धों की गणना की शुरुआत वर्ष 2016 से की गई थी। प्रदेश में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से 4 प्रजातियां स्थानीय एवं 3 प्रजाति प्रवासी हैं। गिद्धों की गणना करने के लिए शीत ऋतु का अंतिम समय सही रहता है। इस दौरान स्थानीय एवं प्रवासी गिद्धों की गणना आसानी से हो जाती है। वर्ष 2019 की गणना में गिद्धों की संख्या 8 हजार 397, वर्ष 2021 में 9 हजार 446 और वर्ष 2024 में बढ़कर 10 हजार 845 हो गई थी।

**साल में दो बार होगी गिनती:** अबकी बार गिद्धों की गिनती साल में दो बार होगी। शीतकालीन गिद्ध गणना 17, 18 और 19 फरवरी को हो चुकी है, जबकि ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना 29 अप्रैल को की जाएगी। पहले चरण में गिद्धों की गिनती सुबह 7 से 8 बजे तक हुई। ऐसे स्थान, जहां पर ऊंची क्लिप्स (चट्टान) है, उन स्थानों पर अधिकतम 9 बजे तक गिनती की गई। केवल बैठे हुए गिद्धों की ही गिनती की गई है।

### गिद्धों के बारे में जानिए

भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में व्हाइट रम वल्चर यानी, सफेद पीठ वाले गिद्ध भी हैं। वन विहार में अभी 100 से ज्यादा गिद्ध हैं। गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना नेशनल पार्क में है। यहां 900 से अधिक गिद्ध हैं। यहां पर लाल सिर वाला गिद्ध भी पाया जाता है। इसे एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काला गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध भी कहा जाता है। इसे पन्ना टाइगर रिजर्व में आसानी से देखा जा सकता है।

### कभी विलुप्त होने की कगार पर थे गिद्ध

एक्सपर्ट के मुताबिक, गिद्ध जल्दी अपना साथी या मैटिंग पेयर नहीं बनाते हैं। यह पक्षी असल में नर्वस किस्म का जीव है। इस मामले में शर्मिला कहा जा सकता है। गिद्ध कभी विलुप्त होने की कगार पर थे। मप्र सहित देशभर में %धरती के सफाई दूत% की संख्या बुरी तरह घटती जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।

### हरियाणा से लाए गए थे गिद्ध

भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में करीब दो साल पहले हरियाणा से सफेद पीठ वाले 20 गिद्ध लाए गए थे। 1100 किलोमीटर की यात्रा करके यह भोपाल पहुंचे थे। वर्तमान में यह गिद्ध संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की एवरी में है। 20 व्हाइट रम वल्चर (सफेद पीठ वाले गिद्ध) में 5 नर और 5 मादा, 10 सब एडल्ट गिद्ध थे।

### सक्सेस रेट 50प्रतिशत

गिद्ध साल में एक ही बार अंडे देते हैं। साइज में यह मुर्गी के अंडे से तीन गुना बड़े होते हैं। मई-जून से अक्टूबर के दौरान मैटिंग सीजन और अंडे देने का समय होता है। अंडे से बच्चे जीवित निकलने का सक्सेस रेट 50 माना जाता है। यही वजह है कि आधे अंडे विकसित नहीं होते हैं। अंडे से 55 दिन में बच्चा निकलता है। चार महीने बच्चा घोंसले में रहता है। फिर वह उड़ने के लिए तैयार हो जाता है।

### इसलिए कम हो गई थी गिद्धों की संख्या

एक आंकड़े के अनुसार, वर्ष 1990 से 92 में भारत में 4 करोड़ गिद्ध थे। साल दर साल ये संख्या कम होती गई। पशुओं को दर्द, सूजन आदि के दौरान डायक्लोफेनाक दवा दी जाती है। इनके खाने के बाद मरने वाले पशु या जानवर का मांस गिद्ध खाते हैं। दवा के प्रभाव से गिद्धों की ज्यादा मौत हो जाती है। यह दवा प्रतिबंधित की गई है।

### जिले के 735 गिद्धों में से 309 का निवास यहीं

## गिद्धों का सुरक्षित ठिकाना बने बकस्वाहा के जंगल

जागत गांव हमार, छतरपुर।

मध्य प्रदेश वन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मप्र भोपाल के निर्देशन में 2024-25 के गिद्ध गणना अभियान के तहत छतरपुर जिले में तीन दिनों तक गिद्धों की गणना की गई। जिले के छह वन परिक्षेत्रों में कुल 735 गिद्धों की पहचान हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 अधिक हैं। विशेष रूप से बकस्वाहा वन क्षेत्र में सबसे अधिक 309 गिद्ध और 109 घोंसले पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र गिद्धों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। गणना के दौरान भारतीय गिद्ध, राज गिद्ध और इजिप्शियन गिद्ध जैसी विभिन्न प्रजातियाँ पाई गईं। बकस्वाहा में सबसे अधिक प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई। वनमंडलाधिकारी सर्वेश सोनवानी ने बताया कि गिद्ध मृत प्राणियों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बकस्वाहा का घना जंगल, उपयुक्त जलवायु और पर्याप्त भोजन गिद्धों के लिए आदर्श आवास है। इस बार निवार और चंदनपुरा जैसे नए इलाकों में भी गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

**संख्या में निरंतर वृद्धि** - पिछले वर्षों की तुलना में गिद्धों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2019 में छतरपुर जिले में 514 गिद्ध थे, जिनमें से 209 बकस्वाहा में थे। 2024 में यह संख्या 709 हो गई, जिसमें से 299 गिद्ध बकस्वाहा में दर्ज किए गए। 2025 में जिले में कुल 735 गिद्धों की गणना हुई, जिनमें से 309 बकस्वाहा में पाए गए।

### सकारात्मक संकेत

गिद्धों को पर्यावरण का स्वच्छता प्रहरी माना जाता है, और उनकी संख्या में वृद्धि पर्यावरण के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संतुलन का संकेत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया पर गिद्धों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई और इसे राज्य के संरक्षण प्रयासों की सफलता बताया। बकस्वाहा के घने जंगल और सुरक्षित वातावरण ने गिद्धों के लिए एक आदर्श आवास स्थल प्रदान किया है, जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

### -पशुगणना में पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा

# मई तक पूरी हो जाएगी पशुओं की गिनती

जागत गांव हमार, भोपाल।

देश में पशुओं को गिनने (पशुगणना) का काम जोर-शोर से चल रहा है। जनगणना की तरह से पशुगणना भी हर पांच साल बाद की जाती है। इसी के आधार पर तमाम तरह की स्कीम बनती हैं और रिसर्च होती है। लेकिन इस बात की पशुगणना कुछ खास है। जैसे पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ऐप पर पशुगणना हो रही है। इतना ही नहीं पहली बार पशुगणना में कुत्तों और छुट्टा गायों को भी शामिल किया गया है। वहीं कुछ नई नस्लों का भी इसमे शामिल किया गया है। पशुपालन और डेयरी सेक्रेटरी का कहना है कि पशुगणना के मई तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं जून में पशुगणना के आंकड़े यानि इसकी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। 21वीं पशुगणना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी। पशुगणना के लिए करीब एक लाख लोगों को लगाया गया है। पशुगणना का करीब 25 फीसद काम पूरा हो चुका है।

### पशुगणना की कुछ खास बातें

- पशुगणना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक पशुगणना होगी।
- गाय की 53 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- भैंस की 20 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- भेड़ की 45 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- बकरी की 39 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- घोड़ों की आठ नस्लों की गिनती की जाएगी।
- गधों की तीन नस्लों की गिनती की जाएगी।
- सूअर की 14 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- कुत्तों की तीन नस्लों की गिनती की जाएगी।
- मुर्गे की 20 नस्लों की गिनती की जाएगी।
- बतख की तीन नस्लों की गिनती की जाएगी।
- मेल और फीमेल के आधार पर गिनती होगी।
- छुट्टा गाय पहली बार गणना में शामिल होंगी।
- 10 जुलाई से लेकर नौ अगस्त तक सभी राज्यों को ट्रेनिंग दी गई।
- स्ट्रीट डॉग को भी पहली बार गणना में शामिल किया गया।

### मोबाइल ऐप से ये होगा फायदा

मंत्रालय का कहना है कि पशुगणना के लिए मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की कई वजह हैं। जैसे इससे आंकड़े बहुत सटीक आएंगे, जिसका फायदा ये होगा कि डेयरी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पॉलिसी और पशुओं की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बनने वाली योजनाओं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।

## छुट्टा गौवंश के लिए बनाए जाएंगे 10 हजार आश्रय

जागत गांव हमार, भोपाल।

छुट्टा गौवंश को सुरक्षित आश्रय स्थल देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तेज गति से काम कर रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि गौवंशो के रहने के लिए आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और अब इनकी संख्या बढ़ाकर 10 हजार की जाएगी। कहा गया है कि छुट्टा गौवंश के चारा और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। वर्तमान में हर गौशाला को प्रति गौवंश के चारा आदि की व्यवस्था के लिए 40 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ग्राम उमरिया में 53 एकड़ में गौशाला परियोजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संतो की नगरी जबालीपुरम धन्य हुई है। यह आनंद का धाम बना है। जिले में अत्याधुनिक गौ-शाला बनाये जाने की नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

**गौशालायों की संख्या 10 हजार तक पहुंचाएंगे** - राज्य के बड़े महानगरों की तरह अन्य बड़ी नगर निगम और नगर पालिकाओं में गौ-शालाओं का निर्माण कर इनकी संख्या को 10 हजार तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर के विकास के लिए 187.43 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय स्तर पर गौ-शालाएं खुलेगी, जिनमें अधिक आयु की निराश्रित, अशक्त गौ-वंशों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

### एमपी सहित देश के सात राज्यों में शुरू हो रही खरीद प्रक्रिया

# एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 15 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

जागत गांव हमार, भोपाल।

गेहूं की सरकारी खरीद अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही है। कई राज्यों ने गेहूं की खरीद पर किसानों को बोनस देने की भी घोषणा की है। जबकि, केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं के एमएसपी पर भी 150 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1 मार्च 2025 से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। इसके अलावा भी कई राज्यों में 1 मार्च और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। हालांकि, किसानों को गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जनवरी 2025 से चल रही है। राज्य सरकारों ने किसानों से एमएसपी पर गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करने की अपील की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्यान्न खरीद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 7 राज्यों ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। 7 राज्यों में 20 फरवरी 2025 तक 9,28,500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, 24 फरवरी तक यह आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है।

## राज्यवार गेहूं की सरकारी खरीद की तारीख

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए क्रय केंद्र बनाने और रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 से शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई राज्य इस बार 1 अप्रैल से पहले खरीद शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में बीते साल 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। इस बार भी 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने की संभावना है। जबकि, सरसों की खरीद 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। बाकी राज्यों में भी 1 अप्रैल से हर हाल में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी।

## कहां कितने किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

खाद्यान्न खरीद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 20 फरवरी तक हरियाणा में 5,66,546 से अधिक किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उधर उत्तर प्रदेश में 2,27,486 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं को एमएसपी पर बिक्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य सरकारों ने बोनस देने की घोषणा भी की है।

## गेहूं की बंपर खेती और रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान

रबी सीजन में गेहूं की बंपर बुवाई की गई है। 27 जनवरी 2025 तक गेहूं बुवाई के सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई है, जो बीते साल 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 9 लाख हेक्टेयर अधिक है। अधिक खेती के साथ ही गेहूं के अधिक उत्पादन का अनुमान जताया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वर्ष में गेहूं उत्पादन टारगेट 1150 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। यह फसल वर्ष 2023-24 जुलाई-जून के दौरान रिकॉर्ड 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है।

### कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

# प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित उद्योग लगाएं जाएंगे

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पडने वाले विपरीत प्रभाव से संरक्षण के लिये जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती करने का लक्ष्य तय कर कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्षों में जैविक-प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर पाँच लाख हैक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को दिलाने के लिये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट-बाजार लगाए जाएं। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकासखंड विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह स्थल पर एक जिला एक उत्पाद तथा विभिन्न विभागों और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरा विश्व प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यकारी प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए मध्यप्रदेश की ओर देख रहा है। नवीन तकनीकों से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो होना चाहिये किन्तु पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती से प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह वर्ष उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। कृषि प्रधान राज्य होने से यहाँ खेती को साथ लेकर उद्योग नीतियां लागू करना आवश्यक है। इसीलिये राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन जिलों में औद्योगिक दर कम हैं, वहां कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की देश के दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि तथा आय वृद्धि के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। कृषि उत्पादकों को सब्जी उत्पाद निर्यात करने पर केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से ट्रान्सपोर्ट व्यय दिया जा रहा है। किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिये कृषक उत्पादक संगठनों तथा स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से चलाए जा रहे अभियान को गति दी जाए।

## गहन विचार मंथन किया जाएगा

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी अनुपम राजन विशेष रूप से उपस्थित थे। सचिव कृषि एम. सेल्वेन्द्रन ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन संचालक कृषि अजय गुप्ता ने किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन विचार मंथन किया जाएगा। इसमें कृषि वैज्ञानिकों, जैविक खेती विशेषज्ञों, कृषक उत्पादक संगठनों, प्रगतिशील किसानों तथा कृषि अधिकारियों के बीच निष्कर्षात्मक संवाद से प्रदेश की जैविक नीति को विकसित करने के प्रयास किये जाएंगे।

## जैविक उत्पादन नीति बनाई जाएगी

कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि आयोजित कार्यशाला के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों की कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर जैविक उत्पादन नीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में 9 सेवा प्रदाताओं से एमओयू किये गए हैं। एपीडा के अनुसार प्रदेश में जैविक खेती का रकबा 11.48 लाख हैक्टेयर है। वन क्षेत्र मिलाकर प्रदेश में कुल 20 लाख 55 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। किसानों को खेत में ही अवशेष प्रबंधन के लिए 42 हजार 500 से अधिक कृषि यंत्र भी वितरित किये गए हैं। इससे पराली जलाने की प्रवृत्ति में कमी आई है।

### उद्यानिकी मंत्री कुशवाह द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ

# कृषि-उद्यानिकी उत्पादों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित

जागत गांव हमार, भोपाल।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद को बेहतर मार्केट उपलब्ध हो सके, इसके लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की अधिकाधिक स्थापना के लिये भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स द्वारा रुचि ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार-भारत सरकार के साथ मिलकर उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध करायेगी। उन्होंने यह बात शनिवार को भोपाल हाट बाजार में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कही।

इस अवसर पर कमिश्नर उद्यानिकी श्रीमती प्रीति मैथिल, सहायक कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार श्री अक्षय याकूब सहित किसान भाई, एफपीओ के सदस्य उपस्थित थे। मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी और कृषि फसलों के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के बाहर के खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों को राज्य शासन उद्यम निवेश नीतियों के तहत पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया जायेगा। उन्होंने उद्यानिकी फसलों के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किये। सहायक कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार श्री अक्षय याकूब ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन से जुड़े किसानों को आधुनिक विपणन तकनीकों से अवगत कराना, सहकारी संस्थानों की भूमिका, एग्री-बिजनेस के अवसरों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण एवं शहरी बाजारों के बीच तालमेल स्थापित करना शामिल है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ एगमार्क सर्टिफिकेशन, आधुनिक विपणन प्रणाली, मूल्य संवर्धन प्र-संस्करण भंडारण, निर्यात तथा ई-बाजार जैसे पहलुओं पर विस्तृत व्याख्यान दिये गये। इसके अलावा कार्यशाला में किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें नवीनतम कृषि विपणन नीतियों और योजनाओं से अवगत कराया गया। कार्यशाला में नाबार्ड, म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड, बैंकों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

# मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाः कृषि पद्धतियों में बदलाव का एक दशक

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की थी। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल देश भर में सभी प्रमुख भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान और मानकीकृत प्रारूप में किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति शामिल होती है, अथाज़्त् नाइट्रोजन, फ़ॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर (मैक्रो-पोषक तत्व), जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन (सूक्ष्म पोषक तत्व) और पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन) ।

इसके आधार पर, कार्ड खेत के लिए आवश्यक उर्वरक अनुशंसाओं और मिट्टी संशोधन को भी बताएगा। मिट्टी के नमूने आम तौर पर साल में दो बार लिए जाते हैं, क्रमशः रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई खड़ी फसल न हो।

ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) के लिए दिशा-निर्देश जून 2023 में जारी किए गए थे। वीएलएसटीएल की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों यानी ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। लाभार्थी/ग्राम स्तरीय उद्यमी एक युवा होना चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ्मीओ) को भी वीएलएसटीएल के रूप में नामांकित किया जा सकता है। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसईएंडएल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के 20 स्कूलों (10 केन्द्रीय विद्यालय और 10 नवोदय विद्यालय) में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को टिकाऊ कृषि प्रथाओं के लिए मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। इन स्कूलों में 20 मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। कार्यक्रम के अंतर्गत, स्कूली छात्रों द्वारा मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए और छात्रों द्वारा मिट्टी का परीक्षण भी किया गया और एसएचसी तैयार किए गए। छात्रों ने उर्वरक और फसल की सिफारिश के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के बारे में भी किसानों को शिक्षित किया।

2024 तक, 1020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं, 1000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और 125,972 छात्र नामांकित हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से ' मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता ' नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।

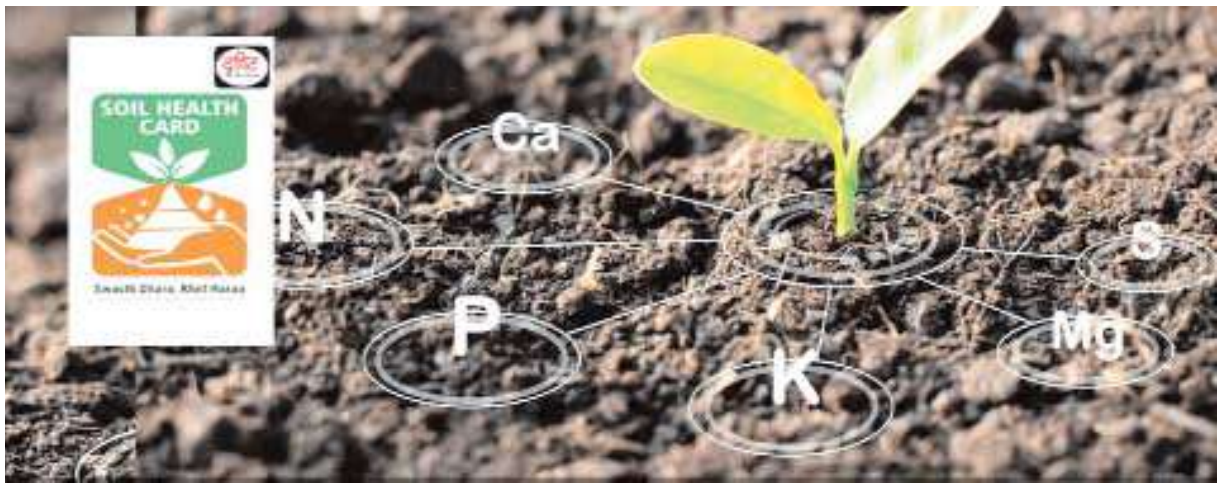


**प्रौद्योगिकी प्रगतिः एसएचसी मोबाइल ऐपः** मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक पहुँच को और आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने 2023 में नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में तकनीकी हस्तक्षेप किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को नया रूप दिया गया और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ एकीकृत किया गया ताकि सभी परीक्षण परिणामों को कैप्चर किया जा सके और मानचित्र पर देखा जा सके। योजना के कार्यान्वयन/निगरानी को सुचारू बनाने और किसानों को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ लैस किया गया है जैसे-

मिट्टी के नमूने एकत्र करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी/संचालक के लिए नमूना संग्रह क्षेत्र को सीमित करना। स्थान के अक्षांश और देशांतर का स्वतः चयन। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, भू-मानचित्रित प्रयोगशालाओं से सीधे पोर्टल पर सभी नमूनों के नमूने और परीक्षण परिणामों को जोड़ने के लिए क्यूआर कोड तैयार करना।

यह एप्लीकेशन पूरे भारत की ग्राफिक जानकारी प्रदान करता है और साथ ही कई स्तरों पर राज्य सीमा, जिला सीमा, तालुका सीमा, पंचायत सीमा और भूकर सीमा भी दिखाता है। नई प्रणाली अप्रैल 2023 में शुरू की गई थी और अब मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब इस नए पोटज़्ल पर बनाए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्डों के डिजिटलीकरण के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा वेब आधारित कार्य प्रवाह अनुप्रयोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल डिजाइन और विकसित किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने पिछले एक दशक में भारत में कृषि पद्धतियों को बदल दिया है। 2015 से, इसने किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति और इष्टतम उर्वरक उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी देकर सशक्त बनाया है, जिससे टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिला है और फसल उत्पादकता में सुधार हुआ है। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी पहलों ने छात्रों और स्थानीय समुदायों के बीच मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। एक मजबूत मोबाइल ऐप के साथ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया ने पहुँच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है। जैसे-जैसे यह योजना विकसित होती है, यह टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है।

# सिर्फ वृक्षारोपण से हासिल नहीं होगा कार्बन कैप्चर का लक्ष्यः अध्ययन

तेजी से बढ़ने वाली फसलें लगाना, उत्सर्जित सीओ2 को कैप्चर उसे संग्रहित करना, वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को हटाने और लंबे समय तक दुनिया भर में तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के समाधान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन शोध पत्र के हवाले से शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर यह मौजूदा खेती की जमीन से अलग हिस्से पर किया जाता है, तो यह जीवमंडल की स्थिरता को खतरे में डालता है।

कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (पीआईके) के द्वारा किए गए एक अध्ययन में ऐसे नए जलवायु वृक्षारोपण की क्षमता का एक आंकड़ा दिया गया है। इसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायोएनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। अध्ययन में न केवल कार्बन संतुलन बल्कि धरती की अन्य सीमाओं का भी आकलन किया गया है। पौधों की प्रजातियों की उत्पादकता के बारे में अध्ययन की मान्यताओं के अनुसार, समय के साथ कोई नई किस्में नहीं हैं। मध्यम जलवायु परिवर्तन मौजूदा खेती की जमीन के बाहर 2050 में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्षमता 20 करोड़ टन से कम होने के आसार हैं। जो कि कई जलवायु परिदृश्यों में अनुमान से काफी कम है।

इसका मतलब यह है कि अगर हम कार्बन हटाने की इस पद्धति पर भरोसा करना चाहते हैं, न कि हवा छानने की प्रणाली जैसे संभावित विकल्पों पर, तो हमें मौजूदा खेती की जमीन का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी। यह तभी संभव है जब हमारी खाद्य प्रणाली में बदलाव हो और अन्य बातों के अलावा पशु उत्पादों पर कम निर्भरता हो।

शोध में कहा गया है कि शोध टीम ने धरती की सीमाओं की अवधारणा से शुरुआत की, जिसे 2009 में विकसित किया गया था। सीमाएं उन नौ प्रक्रियाओं की सीमाओं की बात करती हैं जो मनुष्य जीवन का आधार बनती हैं। इसमें जलवायु से लेकर जंगलों और महासागरों की स्थिति तथा जैव विविधता तक शामिल है। शोध में कहा गया है कि छह सीमाओं का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है। उनमें से चार भूमि से संबंधित हैं और इस प्रकार जलवायु वृक्षारोपण के आवंटन और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक हैं, वे नाइट्रोजन में बढ़ोतरी करने, मीठे या ताजे पानी के चक्र, जंगलों के काटे जाने और जैव विविधता में गिरावट के कारण बायोस्फीयर के नुकसान से संबंधित हैं।

नया अध्ययन पहला व्यवस्थित, प्रक्रिया-आधारित मॉडलिंग प्रदान करता है, अगर इन अहम सीमाओं को और अधिक पार नहीं किया जाता है तो बीईसीसीएस क्षमता कैसे सीमित होगी।

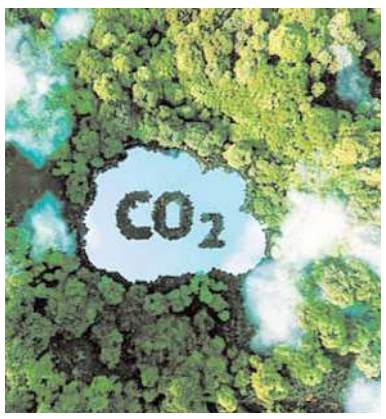


शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि कंप्यूटर सिमुलेशन पीआईके द्वारा विकसित बायोस्फीयर मॉडल के अब तक के सबसे परिष्कृत प्रयोगों में से एक है। यह वर्तमान जलवायु चर्चा पर एक अहम नजरिया प्रदान करता है, इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान में 1.5 डिग्री की सीमा पार हो रही है। जलवायु संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में, हमें न केवल सार्वजनिक नीतियों के सीओ2 संतुलन को देखना चाहिए, बल्कि अन्य ग्रहीय सीमाओं पर भी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी प्रणाली का लचीलापन कई परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

यदि आज की कृषि के बाहर सभी जैव-भौतिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रों को बदल दिया जाए, तो जलवायु वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन हटाने की क्षमता अधिकांश जलवायु परिदृश्यों में अनुमान की तुलना में काफी अधिक होगी। ये परिदृश्य 2050 में औसतन लगभग 7.5 अरब टन कार्बन हटाने का अनुमान लगाते हैं। दुनिया भर के तापमान को 1.5 डिग्री के बजाय दो डिग्री तक सीमित करने के लिए अक्सर बीईसीसीएस आधारित तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरकों से नाइट्रोजन की मात्रा को सीमित करने से यह सैद्धांतिक ऊपरी सीमा के सापेक्ष 21 फीसदी कम हो जाता है। मीठे पानी की प्रणालियों का संरक्षण इसे 59 फीसदी तक कम कर देता है। जंगलों के काटे जाने की सीमाओं के कारण 61 फीसदी की कमी होती है। जैवमंडल के आगे के नुकसान को 93 फीसदी तक टाला जा सकता है। शोध के मुताबिक, यह मानते हुए कि सभी चार ग्रहीय सीमाओं का सम्मान किया जाता है, मौजूदा जंगलों के लिए स्पष्ट सुरक्षा के साथ, मॉडल अध्ययन 2050 में 20 करोड़ टन से कम सीओ2 हटाने की क्षमता की ओर इशारा करता है।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि पशु उत्पादों का कम उत्पादन और उपभोग न केवल कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करके जलवायु में मदद करता है, बल्कि यह दुर्लभ संसाधनों के लिए संघर्ष को भी आसान बनाता है, जिससे पूरी पृथ्वी प्रणाली की रक्षा होती है।

## उपजाऊ मिट्टी के लिए केमिकल खाद का इस्तेमाल घटाना जरूरी

खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए केमिकल खादों का इस्तेमाल घटाकर पूरी तरह बंद करना होगा। पीएचडी चैंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कृषि पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सिंचाई तकनीक को मजबूत करने के साथ ही नए इनोवेशन जरूरी हैं। सूखा और कीटों से निपटने में सक्षम बीजों का विकास करना होगा, ताकि भविष्य में कृषि का विकास बेहतर बना रहे। उद्योग निकाय पीएचडी चैंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कृषि पर जारी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सिंचाई तकनीक को मजबूत करने के लिए और अधिक इनोवेशन करने जाने चाहिए ताकि कृषि को उतार- चढ़ाव वाले मानसून के असर मुक्त किया जा सके। संस्थान ने यह भी कहा कि केमिकल खादों के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करना जरूरी है।

**केमिकल खादों का इस्तेमाल घटाया जाएः** पीएचडी चैंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से अधिक स्थिरता को लागू कर रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि कृत्रिम उर्वरकों के इस्तेमाल को घटाया जाए और फिर पूरी तरह बंद किया जाए। कहा गया कि विज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी में प्रगति आज कृषि के सामने मौजूद बहुआयामी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अहम है।

**किसानों को कृषि तकनीक ट्रेनिंग की व्यवस्था होः** रिपोर्ट में कहा गया है कि सूखा प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी फ़सलों किस्मों को विकसित करना जरूरी है। कृषि-पूर्व तकनीक और डिजिटल खेती सॉल्यूशन को विकसित करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने से उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सकती है। किसानों को तकनीक और ट्रेनिंग दिलाने के लिए पहल शुरू की जानी चाहिए।

**जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करे आईसीएआरः** सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने के लिए कम से कम एक विशेषता वाली किस्मों को विकसित करने को कहा है। इन किस्मों में सूखा, गमीज या बाढ़ जैसी स्थितियों में सहनशील बने रहने की क्षमता के साथ विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पिछले साल अगस्त में जलवायु अनुकूल बीजों की 109 किस्में भी जारी कीं, जबकि 2025-26 के बजट में हाईब्रिड बीजों पर एक टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की गई है।

**फसल नुकसान घटाने पर फ़ोकस करना होगाः** रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल कटाई से पहले और फ़सल कटाई के बाद की गतिविधियों में

### एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

# एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

अखंड यादव, टीकमगढ़।

केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, मुरैना द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी.एम.) पर दो दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के स्थानीय किसानों, कीटनाशक विक्रेताओं और राज्य कृषि कर्मचारियों को आईपीएम की नवीनतम तकनीकों और विधियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम मे कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. बीएस किरार ने जिले की प्रमुख फसलों मे आईपीएम के महत्व के विषय में बताया गया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आईपीएम के बारे में जागरूक करने और उन्हें इसे

लागू करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान टीकमगढ़ जिले के उपसंचालक कृषि अशोक शर्मा द्वारा टीकमगढ़ जिले के कीट व्याधि के बारे मे जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक (मात्स्यिकी) डॉ. सतेंद्र कुमार द्वारा किया गया उन्होंने कहा कि आईपीए. किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। यह किसानों को उनकी फसलों को नाशीजीवों से बचाने और उनकी उपज को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

## समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन

केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र के प्रभारी अधिकारी सुनीत कुमार कटियार ने कहा कि आईपीएम को बढ़ावा देना केंद्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को आईपीएम के बारे में नवीनतम जानकारी और तकनीक प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डा. यूएस धाकड, डा. सुनिल कुमार जाटव ने सक्रिय रूप से योगगदान दिया उन्होंने केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, मुरैना के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से आईपीएम से संबंधित अपने प्रश्नों और समस्याओं पर चर्चा की। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने और आई.पी.एम. को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया।

### किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के साथ चर्चा सत्र का आयोजन

# मुरैना के किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र का किया भ्रमण, जाना खेती का बेहतर तरीका

जागत गांव हमार, टीकमगढ़।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा मुरैना के किसानों के एक समूह ने कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण किया। इस भ्रमण का उद्देश्य किसानों को कृषि की नई तकनीक से अवगत कराना एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शित इकाइओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था। डॉ. बीएस किरार, प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ ने किसानो को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को बेहतर खेती के तरीके अपनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को नवीनतम तकनीकों और विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

डॉ. सतेंद्र कुमार, वैज्ञानिक (मात्स्यिकी), कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ ने किसानों को केंद्र में स्थित विभिन्न इकाइयों जैसे कि क्रोप कैफेटेरिआ, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, अजोला, बीज उत्पादन इकाई, जैविक खेती इकाई, मशरूम उत्पादन इकाई, और पॉलीहाउस आदि का दौरा कराया। उन्होंने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से इन इकाइयों में संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

किसानों की कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदर्शित विभिन्न तकनीकों और विधियों के बारे में विशेष जानकारी हेतु भ्रमण के पश्चात किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के साथ चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा सत्र मे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. आरके प्रजापति वैज्ञानिक (पादप रोग), डा. यूएस धाकड वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान), डा. सुनिल कुमार जाटव वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), इंद्र देव सिंह वरिष्ठ

तकनीकी अधिकारी (मृदा विज्ञान) और जयपाल छिगारहा, वाय पी 2, निकरा परियोजना ने किसानो से कृषि से संबंधित अपनी समस्याओं और मुद्दों पर भी चर्चा की। वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान करने और उन्हें बेहतर खेती के तरीके अपनाने के बारे में मार्गदर्शन दिया।

## किसानों ने जानी केवीके की गतिविधियां

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, मुरैना के प्रबंधक प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने कहा कि यह भ्रमण किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों को इन तकनीकों और विधियों को अपनी खेती में अपनाने से लाभ होगा। यह भ्रमण महात्मा गांधी सेवा आश्रम और कृषि विज्ञान केंद्र के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। इस भ्रमण के माध्यम से किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न इकाइयों और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

# कृषि के नवाचार एवं बेहतर कृषि तकनीकी के लिए मिला सम्मान

जागत गांव हमार, भोपाल।

कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ शेखर सिंह बघेल के मार्गदर्शन में इंजीनियर कुमार सोनी एवं डॉ जी के राणा के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर द्वारा आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी 18 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस किसान मेला एवं प्रदर्शनी में 50 से अधिक कृषि जानकारी हेतु स्टाल लगाए गए जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के द्वारा कृषि तकनीकी के नवाचार एवं कृषि जानकारी से संबंधित प्रचार प्रसार हेतु स्टॉल लगाया गया जिसमें गेहूं चना मटर सरसों अलसी मक्का धान कुसुम सूरजमुखी श्रीअन्न आदि के नवीनतम बीज कृषि तकनीक एवं नवाचार की साथ ही केंचुआ खाद मुनगा बेगानी सेम जैव उर्वरक जैविक खेती पशुपालन इकाई की मॉडल एवं सीड बॉल का भा.कृ.अनु.प. खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर (म.प्र.) द्वारा आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी 2025 में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के द्वारा उच्च तकनीकियों एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादों का प्रदर्शन किया गया शासकीय स्टॉल श्रेणी में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी को द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेला की उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह एवं निदेशक डी डब्ल्यू आर डॉ जे एस मिश्रा द्वारा केवीके के स्टॉल का निरीक्षण किया और कार्यों की सराहना की।

### जेएनकेवीवी की जेएस 24-34 किस्म की मध्य भारत में खेती के लिए पहचान करने प्रस्ताव को मंजूरी

# सोयाबीन पर वार्षिक समूह बैठक, कई राज्यों के वैज्ञानिकों लिया भाग

जागत गांव हमार, इंदौर।

सोयाबीन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) की तीन दिवसीय वार्षिक समूह बैठक गत दिनों चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में सोयाबीन उगाने वाले प्रमुख राज्यों के 60 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तिलहन और दलहन), डॉ. संजीव गुप्ता और इंदौर स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. के.एच. सिंह ने 2024-25 के दौरान देश भर में किए गए विभिन्न परीक्षणों और प्रयोगों की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की।

डॉ बी यू दुपारे, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष प्रेस एवं मीडिया समिति,भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार

समापन सत्र के दौरान, सीसीएसएचपीकेवी पालमपुर के कुलपति डॉ. नवीन कुमार ने मानव जाति और पशुधन दोनों के लिए सोयाबीन के महत्व के बारे में जानकारी दी और नए तरीकों और किस्मों का उपयोग करके सोयाबीन खेती की खेती की पद्धतियों और साधनों के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। आईसीएआर एनएसआरआई के निदेशक डॉ. केएच सिंह ने सोयाबीन वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की और हाल के वर्षों में अनुभव की जा रही जलवायु प्रतिकूलताओं के कारण अस्थिर उत्पादकता और आगे की चुनौतियों के लिए अपनी चिंता भी व्यक्त की। इस अवसर पर आयोजित किस्म पहचान समिति की एक विशेष बैठक में जेएनकेवीवी, जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जेएस 24-34 की मध्य भारत में खेती के लिए पहचान करने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

## प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने पर दिया जोर

इस अवसर पर डॉ. संजीव गुप्ता ने खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त सोयाबीन किस्मों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही सोयाबीन में ओलिक एसिड की मात्रा बढ़ाने, तथा कृषकों के स्तर पर सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम और बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने एवं चारकोल रॉट, येलो मोजेक रोग जैसी बीमारियों के लिए प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने का भी आग्रह किया।

### पोल्ट्री-डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ाने और बीमारियों के जोखिम को कम करने का प्रयास

# पशुओं की वैक्सीन और इलाज के लिए पीपीपी मोड पर बनी ये बड़ी योजना

**जागत गांव हमार, नई दिल्ली।**

पोल्ट्री-डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ाने और बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय लगातार कई योजनाओं पर काम कर रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पहली शर्त ये है कि एनीमल प्रोडक्ट पूरी तरह से बीमारी रहित हो और एंटी बायोटिक का इस्तेमाल कम से कम किया गया हो। इसी के चलते मंत्रालय ने हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान पशु चिकित्सा के विकास को लेकर चर्चा हुई। इसमे खासतौर से वैक्सीन प्लेटफॉर्म, पशु चिकित्सा में काम करने के तरीकों का डवलपमेंट, संस्थागत बुनियादी ढांचे और खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्रों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की मदद से पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

### पशु चिकित्सा में इन मुद्दों पर होगा काम

- जिला स्तर पर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- पशु चिकित्सा को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।
- हाईटेक सर्विलांस और एफएमडी फ्री जोन बनाकर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत बनाना।
- पशु चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफार्म की मदद से कार्यबल क्षमता का निर्माण करना।
- टीका श्रृंखला विकसित करके पशु चिकित्सा टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।
- पशु चिकित्सा अनुसंधान, उपचार और विस्तार सेवाओं में पीपीपी नीति ढांचे को परिभाषित करना।

### पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक संरचित संस्थागत ढांचे की जरूरत: डॉ. अभिजीत मित्रा

एनीमल हसबेंडरी कमिश्नर डॉ. अभिजीत मित्रा का कहना है कि पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक संरचित संस्थागत ढांचे की जरूरत है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें। इस मीटिंग में इस तरह के ढांचे को परिभाषित करने के लिए आधार तैयार किया गया है। वहीं ञ्जह्र॥ के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रतिनिधि डॉ. हिरोफुमी कुगिता ने पशु चिकित्सा सेवाओं में भारत के नेतृत्व, नॉलेज शेयरिंग और लैब सहयोग के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं में योगदान देने की क्षमता पर अपनी मुहर लगाई।

### पशु चिकित्सा लैब स्थापित करने की जरूरत: अलका उपाध्याय

डेयरी सक्रेटरी अलका उपाध्याय ने इस मौके पर कहा कि भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 30 फीसद से ज्यादा का योगदान देता है। एनएबीएल मान्यता के साथ पशु चिकित्सा लैब स्थापित करने की जरूरत है। साथ ही रोग निगरानी, कार्यबल क्षमता और टीका उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग भी जरूरी है। क्योंकि डब्लूएचओ की बैठक में पशु चिकित्सा सेवाओं में पीपीपी जुड़ाव के लिए एक मंच तैयार किया गया है। इस मंच से एक ऐसा रोडमैप तैयार किया जाएगा जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को बढ़ाता है। पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विस्तार करता है। पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी सिस्टम तय करता है। इसी के चलते पशु चिकित्सा सेवाओं में दीर्घकालिक निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक साल के अंदर एक पशु चिकित्सा संबंधी पीपीपी नीति विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

### गौमूत्र और गोबर पर होगा शोध

# उप्र के स्कूलों पढ़ाई जाएगी 'गाय शिक्षा' योगी सरकार 5 रुपये/लीटर खरीदेगी

**जागत गांव हमार, लखनऊ।**

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा, देखभाल और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने हाल ही में 'गाय योजना' को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नई योजना से न केवल गायों की सुरक्षा और देखभाल में सुधार होगा, बल्कि इससे शिक्षा, अनुसंधान और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की पहल से आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के साथ-साथ पशुपालन को भी मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। बता दें कि राज्य सरकार की गाय योजना के तहत गायों को शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान से जोड़ा जाएगा। डेयरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई। इस योजना के अनुसार, स्कूलों के पाठ्यक्रम में गायों से जुड़ी शिक्षा को शामिल किया जाएगा।

**स्कूलों में होगी 'गाय शिक्षा'-** सरकार ने मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु अनुसंधान संस्थान को स्कूलों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, ताकि इसे स्कूलों में आसानी से शामिल किया जा सके।

**गौमूत्र और गोबर पर होगा शोध-**

सरकार ने 'देशी' गायों के गौमूत्र को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे इसका उपयोग चिकित्सा अनुसंधान और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाएगा। इसके अलावा, गोबर और गौमूत्र से जुड़े अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

### आवारा पशुओं के लिए विशेष योजना

मार्च 2017 में राज्य सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ गई। इसे देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
- राजमार्गों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को रेडियम बेल्ट पहनाई जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
- आवारा गायों के लिए अभयारण्य बनाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत, केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर में 52 हेक्टेयर भूमि पर 5,000 गायों के लिए गौ-अभयारण्य बनाने के लिए 63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

### गौशालाओं का विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य में 7,713 गौशालाओं के माध्यम से 12।43 लाख से अधिक निराश्रित गायों को आश्रय दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त , 543 बड़े गौ-संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 372 पहले से ही कार्यरत हैं। गायों के बेहतर पालन-पोषण के लिए सरकार ने प्रति गाय रखरखाव भत्ता 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.62 लाख गायों की देखभाल के लिए 1.05 लाख लाभाथिज्र्यों को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है.

# बुंदेलखंडी बकरी को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

**भोपाल।** बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण पशुधन प्रजाति, बुंदेलखंडी बकरी को आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल द्वारा एक नई नस्ल की बकरी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। यह घोषणा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई। इस बकरी को मान्यता इसलिए दी गई है, ताकि बुंदेलखंडी बकरी के संरक्षण और विकास प्रयासों को बल मिलेगा। अनुसंधान के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय बकरी पालकों की आजीविका में सुधार होगा।

**पहचान और विशेषताएं:** यह नस्ल कठोरता और चरम जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसकी मुख्य पहचान और विशेषताएं इस प्रकार हैं। काले रंग के बाल और बेलनाकार शरीर। लंबे पैर, संकीर्ण चेहरा और रोमन नाक। घनी पूंछ और आकर्षक लंबे बाल। लंबी दूरी तक चलने और कठोर इलाकों में चरने की क्षमता। मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली यह बकरी दूध उत्पादन में भी सक्षम है।

### प्रजनन क्षेत्र- संभावनाएं

बुंदेलखंडी बकरी का सबसे शुद्ध रूप मध्य प्रदेश के दतिया जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पाया जाता है। यहां के गांवों में अन्य नस्लों के साथ इनके छोटे झुंड भी देखे जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर आहार और प्रबंधन से इस नस्ल की उत्पादकता और दूध उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है।

### संस्थान का योगदान

इस मान्यता का श्रेय आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं आईजीएफआरआई के निदेशक डॉ. पंकज कौशल के नेतृत्व में किए गए संरक्षण प्रयासों को जाता है।

### राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने को तैयार

विशेषज्ञों का मानना है कि बुंदेलखंडी बकरी को नई मान्यता देने से बकरी पालकों की आथिज्र्क स्थिति में तो सुधार होगा, साथ ही अन्य कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि- बेहतर प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्पादकता में वृद्धि होगी। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को नई दिशा मिलेगी।

### उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ख़ास इलाके की मुख्य नस्ल

# किसानों को मालामाल कर सकती है भदावरी भैंस, जानें खासियत

**भोपाल।** शहरों में गाय और भैंस के दूध की मांग समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग हेल्दी रहने के लिए डाइट में कई तरह की चीजों को शामिल करते हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है।

ऐसे में अगर आप भी किसी रोजगार की तलाश में हैं तो आप भैंस की उन्नत नस्लों का पालन कर लाखों की कमाई कर सकते हैं। भैंस की कुछ नस्लें ऐसी हैं जो आपको लाखों की कमाई करवा सकती हैं। उन नस्लों में से एक है भदावरी नस्ल। भैंस की यह नस्ल मथुरा, आगरा, इटावा में अधिक पाई जाती है। क्या है इस नस्ल की खासियत और कैसे किसान इस नस्ल का पालन कर अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

**भैंसों की संख्या में गिरावट:** भारत में कुल दूध उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत यानी करीब 20 मिलियन टन दूध भैंस पालन से आता है। हम बात कर रहे हैं भदावरी भैंस की, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ख़ास इलाके की मुख्य नस्ल है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इस नस्ल की भैंसों की संख्या में कमी देखी गई है। लेकिन आपको बता दें, अन्य भैंसों के मुकाबले भैंस की इस नस्ल को पालना काफी आसान है और इसका मुख्य कारण भदावरी भैंस का कम वजन और छोटा आकार है।



**आसानी से करें इस नस्ल का पालन-** भूमिहीन किसान और गरीब पशुपालक भी कम संसाधनों में भदावरी भैंस को आसानी से पाल सकते हैं। भदावरी भैंस किसी भी जलवायु में आसानी से ढल जाती है और इस नस्ल के पशु कम खाना खाकर भी अच्छी गुणवत्ता वाला दूध दे सकते हैं। हालांकि, पशुपालन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे, पशु के रहने की जगह हवादार होनी चाहिए, पशुशाला को साफ रखें और पशुओं के भोजन और पानी की भी उचित व्यवस्था करें।

### दूध बेचकर करें लाखों की कमाई

**भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा काफी अधिक होती है। जिसके कारण यह बाजार में आसानी से अच्छी कीमत पर बिक जाती है। आपको बता दें कि इसके दूध में 14 से 18 प्रतिशत वसा होती है। यह एक ब्यांत में 800 से 1000 लीटर दूध देती है। ऐसे में किसान एक ब्यांत में आसानी से 6 से 7 लाख रुपये कमा सकते हैं।**

### दिल्ली में तीन दिवसीय 'पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025' का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन

# कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान खेती की आत्मा हैं: शिवराज सिंह चौहान

## विज्ञान और किसान को जोड़ने के लिए हमने लैब टू लैंड प्रयोग शुरू किया है: चौहान

» विकसित भारत तभी बनेगा, जब कृषि उन्नत होगी: शिवराज सिंह चौहान

» बिहार के दरभंगा में मखाना के किसानों से चर्चा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री

**जागत गांव हमार, नई दिल्ली।**

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, आईएआरआई के निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव, उप महानिदेशक डॉ. डीके यादव सहित अन्य अधिकारी- कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खेती की आत्मा किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं भी किसान हूँ, मेरे खेत में कद्दू लगा है, शिमला मिर्च भी है और टमाटर भी हैं। जब क्रॉप बम्पर आती है तो कीमतें कई बार गिरती हैं। मैं फूलों की खेती भी करता हूँ, गेहूँ और धान की खेती भी करता हूँ। मैं ऐसा किसान नहीं हूँ कि मंत्री हूँ तो साहब बन गया हूँ, मैं महीने में दो बार अपने खेत में पहुँचने की कोशिश करता हूँ।

### उत्पादन बढ़ाना हमारी प्राथमिकता

शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआरए को बधाई देते हुए कहा कि आज जो किस्में दिखाई हैं, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिक दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर एक है उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज है अच्छे बीज। अच्छे बीज की वैरायटी बनाने का काम आईसीएआर कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अच्छे बीज किसानों तक पहुँचें। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड के लिए हम तरीका निकालें कि कैसे वो किसान तक पहुँचें। बीज पहुँचाने के लिए विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा। लैब टू लैंड, यह हमने एक प्रयोग शुरू किया है आधुनिक कृषि चौपाल। उन्होंने आईसीएआर को निर्देशित किया कि इस काम को अपने हाथ में ले लें। अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल आईसीएआर करेगा। शिवराज सिंह ने बताया कि दूसरा प्रमुख काम है उत्पादन लागत घटाना। उत्पादन बढ़ने से लागत घटती है। इस संबंध में कई योजनाएँ भी हैं। उन्होंने बताया कि मैं बिहार में मखाना उत्पादकों के बीच जाऊंगा, मखाना कैसे बोते हैं, वो देखेंगे। इससे पहले मैं सुपारी उत्पादकों के बीच गया था। अभी मैंने पूसा में इंटीग्रेटेड फार्म देखा। एक हेक्टेयर में मछली पालन, मुर्गी पालन, तालाब था। शिवराज सिंह ने कहा कि हमें किसानों की लागत का इंतजाम भी करना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे फल सब्जी के किसान को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि तीसरा कार्य है उत्पादन का ठीक दाम देना। इसके लिए लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य -एमएसपी पर बढ़ोतरी की गई है। किसान का गेहूँ, चावल तो सरकार खरीदेगी ही, मसूर उड़द, तुअर पूरी खरीदी जाएगी। इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, जब उनको अच्छे दाम मिले। किसान जहाँ बेचता है वहाँ सस्ता बिकता है और दिल्ली - मुंबई में आ जाए तो महंगा हो जाता है। अभी टमाटर के रेट कम हो गए हैं। हमने योजना बनाई है कि नाफेड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केंद्र सरकार चुकाएगी, जिससे किसान को ठीक दाम मिलें। शिवराज सिंह ने कहा कि सोयाबीन के रेट घटे तो बाहर से आने वाले तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 27.5प्रतिशत कर दी। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, हमने उसे हटाया और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की। बीच का मुनाफा जो है, वो घटना चाहिए, इसको लेकर हम वर्कआउट कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि हमने तय किया कि लाल मिर्ची को हम एमआइएस योजना के तहत खरीदने की अनुमति देंगे। इसी तरह चौथा प्रमुख कार्य है कि जब प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होती है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मध्यम से मदद करते हैं।

### किसानों को किया सम्मानित

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवोन्मेषी कृषक और अध्येता कृषक पुरस्कारों से किसानों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी खेती में नई तकनीकों को अपनाकर अनुकरणीय कार्य किए हैं। मेले के दौरान किसानों को नवाचारों और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेले में किसानों के लिए उन्नत बीज, जैविक खाद, जलवायु अनुकूल तकनीक, ड्रोन स्प्रे तकनीक, स्मार्ट सिंचाई तकनीक और बाजार लिंकेज जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तीन सौ से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस आयोजन से किसानों को नई तकनीकों को अपनाने, वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करने और अपनी खेती को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है।

### इंदौर के देपालपुर में एनएफडीपी पर पंजीकरण के लिए मोबिलाइजेशन शिविर का आयोजन

# खाद्य सुरक्षा, आजीविका-अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका: केन्द्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन

**जागत गांव हमार, इंदौर।**

खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए मात्स्यिकी पर निर्भर हैं। इसलिए मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए मछुआरों और उद्यमियों का कल्याण एवं उनकी सहायता आवश्यक है। यह बात केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्जकुरियन ने इंदौर जिले के देपालपुर में राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर पंजीकरण के लिए आयोजित मोबिलाइजेशन शिविर को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने संवर्धित झींगा के शीर्ष उत्पादक और जलीय कृषि और मछली के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर दिया। कुरियन ने 2020 में 20,050 करोड़ के निवेश के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और 2023-27 के लिए 6,000 करोड़ की लागत के साथ एक नई उप-योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) को मिली मंजूरी पर चर्चा की। उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए 11 सितंबर, 2024 को लॉन्च किए गए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर भी प्रकाश डाला, जिसमें पहले ही 18 लाख हितधारक पंजीकृत हो चुके हैं।

उन्होंने सभी हितधारकों से एनएफडीपी पर पंजीकरण करने और योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे भारत को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में वैश्विक नेता बनाया जा सके। इसके अलावा, माननीय राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में 25

करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत एक्वापार्क और अनुसंधान केंद्र के महत्व पर जोर दिया। इस एक्वापार्क का उद्देश्य क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, मछली की खपत को बढ़ावा देने और मत्स्य उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए एक फिश पार्लर का उद्घाटन किया गया।

### एनएफडीपी पर पंजीकरण के लिए मोबिलाइजेशन शिविर का आयोजन

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफार्म (एनएफडीपी) पर पंजीकरण के लिए 14 से 22 फरवरी 2025 तक एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित कर रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र हितधारकों से आवेदन प्राप्त करने और पंजीकरण अनुमोदन में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत, मत्स्य विभाग ने 20 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर में राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर पंजीकरण के लिए मोबिलाइजेशन शिविर का आयोजन किया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभागों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से यह प्रयास पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने, अनुमोदन दरों को बढ़ाने और पात्र हितधारकों को पीएमएमकेएसएसवाई के तहत ऋण सुविधा, जलीय कृषि बीमा और प्रदर्शन अनुदान जैसे कई लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश में 60,426 लोगों ने एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

**1500 मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआरों और उद्यमियों ने भाग लिया**

शिविर में 1500 मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआरों और उद्यमियों ने भाग लिया। पंजीकरण आउटरीच कार्य मे सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी के लिए एक मजबूत आह्वान के साथ संपन्न हुआ। यह पहल डिजिटल सशक्ति करण और वित्तीय लाभों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से मछुआरों और मछली किसानों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह अभियान स्थायी विकास को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन क्षेत्र में लगे लोगों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में नारायण सिंह पंवार, मत्स्य कल्याण और मत्स्य पालन विभाग मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, शंकर लालवानी, सांसद, इंदौर और रवि कुमार, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, इंदौर उपस्थित थे।

### वनस्पति तेल आयात पर ड्यूटी बढ़ेगी!

# तिलहन किसानों को अधिक दाम दिलाने के लिए सरकार लेगी बड़ा फैसला

**जागत गांव हमार, नई दिल्ली।**

घरेलू स्तर पर तिलहन की कीमतों में गिरावट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, उन्हें मंडियों में अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को राहत देने इरादे से केंद्र सरकार वनस्पति तेल के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार भारत घरेलू तिलहन कीमतों में गिरावट से जूझ रहे हजारों तिलहन किसानों की मदद के लिए छह महीने से भी कम समय में दूसरी बार वनस्पति तेलों पर आयात कर बढ़ा सकता है। खाद्य तेलों के दुनिया के सबसे बड़े आयातक भारत की ओर से आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने से स्थानीय वनस्पति तेल और तिलहन की कीमतें बढ़ सकती हैं।

केंद्र सरकार फैसला लेती है तो वनस्पति तेल की मांग में कमी आ सकती है और पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल की विदेशों से खरीद कम हो सकती है। सरकारी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि शुल्क बढ़ोत्तरी को लेकर आंतरिक मंत्रालय स्तर का परामर्श पूरा हो चुका है। अब सरकार की ओर से जल्द ही शुल्क बढ़ाए जाने के ऐलान की उम्मीद है।

### तेलों पर कितनी है मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी

रॉयटर्स के अनुसार केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में कच्चे और प्रॉसेस्ड वनस्पति तेलों पर 20 फीसदी मूल सीमा शुल्क लगाया था। संशोधन के बाद कच्चे पाम तेल, कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर 27.5 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया। जबकि, पहले यह 5.5प्रतिशत था, जबकि तीनों तेलों के प्रॉसेस ग्रेड पर अब 35.75 फीसदी आयात शुल्क लागू है।

### महंगाई दर पर सरकार की नजर

एक अन्य सरकारी सूत्र ने बताया कि सरकार निर्णय का असर खाद्य महंगाई दर पर पड़ने को भी ध्यान में रखेगी। समाचार एजेंसी रायटर्स के अनुसार जनवरी महीने में खाद्य महंगाई दर 6.02 फीसदी दर्ज की गई है, जो दिसंबर में 8.39 फीसदी थी। जनवरी में सब्जियों की कीमतों में सालाना आधार पर 11.35 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. अनाज की महंगाई दर 6.50 फीसदी दर्ज की गई। जबकि दालों की कीमतों में 3.80 फीसदी बढ़त रही।

### छतरपुर में जल सहेलियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया वृक्षारोपण

# जल सहेलियां पानी बचाने का कर रही हैं अद्भुत कामः शिवराज सिंह चौहान

- » जटाशंकर धाम में दिलाई मिट्टी और जल संरक्षण की शपथ
- » पानी बचाने के लिए जल सहेलियों का सहयोग लेगी भारत सरकारः शिवराज
- » पेड़ हमें ऑक्सिजन देते हैं, जीवन बचाते हैं, प्रतिदिन पेड़ लगाते हुए मुझे 4 साल पूरे हुए हैंः चौहान
- » लाड़ली बहनों के बाद अब लखपति दीदी अभियान, पक्के आवास के लिए सेल्फसर्वे कर सकते हैं हितग्राही

**जागत गांव हमार, छतरपुर।**

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के जटाशंकर धाम में जल सहेलियों के साथ वृक्षारोपण किया। साथ ही शिवराज सिंह ने वाटरशेड यात्रा और जल सहेलियों की जल यात्रा समापन में सहभागिता कर जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान चौहान ने सभी को मिट्टी और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने जल सहेलियों और उपस्थितजनों से संवाद करते हुए कहा कि हमें जल बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, जल के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। अगर धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है तो पानी बचाना होगा। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह का खजुराहो से लेकर छतरपुर, जटाशंकर धाम तक आम जनता ने भव्य स्वागत किया।

## जल के संरक्षण में जल सहेलियों का सहयोग लिया जाएगा

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पानी बचाने के लिए वाटरशेड यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कितने लोग जुड़ रहे हैं..? सही मायने में यात्रा से जोड़ने वाली तो जल सहेलियां हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब मैं ये तय कर रहा हूँ कि, जल के संरक्षण में जल सहेलियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। इस यात्रा में मेरे साथ भारत सरकार के अधिकारी भी आएंगे और बहनों के साथ मिलकर जल बचाएंगे। जल सहेलियां अद्भुत काम कर रही है। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान मोदी का संकल्प है। हर पात्र व्यक्ति को पक्का आवास दिया जाएगा, उनका पक्के घर का सपना साकार किया जाएगा और इसके लिए फिर से सर्वे शुरू कर दिया गया है। साथ ही नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले जिनके पास दो पहिया वाहन होते थे उन्हें पक्का आवास नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दो पहिया वाहन वाले भी पक्के आवास के लिए पात्र होंगे। इसी तरह पहले जिनकी मासिक आमदनी 10 हजार रूपए से ज्यादा थी वो पक्के आवास के लिए पात्र नहीं होते थे, लेकिन अब 15 हजार की आय वाले भी पात्र होंगे। वहीं ढाई एकड़ सिंचित और 5 एक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी अब पक्का आवास दिया जाएगा। अब पक्के आवास के लिए हितग्राही घर बैठे अपने मोबाईल से खुद भी सर्वे कर सकता है। हितग्राही अपने मोबाईल में एप पर लॉगिन करें, आधार नंबर डालें, पूरी जानकारी भरें और खुद का फोटो खींचकर अपलोड कर दें और हितग्राही का सूची में नाम जुड़ जाएगा।

### बोनस के साथ 1 मार्च से शुरू होगी खरीद

# 81 लाख गेहूं किसानों को एमएसपी से 175 रु. अधिक मिलेगा दाम

**जागत गांव हमार, भोपाल।**

गेहूं किसानों को इस बार अपनी उपज का अधिक दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के दाम को एमएसपी से 175 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। राज्य में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। राज्य में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है और कुछ इलाकों में कटाई भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उपज खरीद के दाम को बढ़ा दिया है। गेहूं खरीद के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है, लेकिन, राज्य सरकार एमएसपी से ज्यादा दाम किसानों को देगी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार किसानों को 175 रुपये का बोनस दिया जाएगा।

### गेहूं खरीद 2600 रुपये दाम पर होगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस वर्ष गेहूं किसानों से 2600 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगीं यानी एमएसपी से 175 रुपये प्रति कुंटल अधिक दाम मिलेगा। राज्य सरकार ने बीते साल 125 रुपये का बोनस गेहूं किसानों को दिया था और किसानों को प्रति कुंटल अधिकतम भाव 2400 रुपये मिला था। लेकिन, इस बार किसानों को अधिक दाम देने की घोषणा की गई है।

### 48 घंटे के अंदर होगा भुगतान

मध्य प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। गेहूं खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे में भुगतान उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों और मंडियों पर किसानों के लिए पानी, छांव आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

### बंपर उत्पादन का अनुमान

मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर गेहूं का रकबा 325 लाख हेक्टेयर है। मंत्रालय का अनुमान है कि इस सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं का उत्पादन 1150 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है।


## जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दडुद्बद्धद्दiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371


# एमएसपी पर गेहूं की बेचने के लिए 2 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

**भोपाल।** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक एक लाख 88 हजार 645 किसानों ने पंजीयन कराया है। 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि समय से पंजीयन करायें। एमएसपी पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिला बुरहानपुर में 10, खरगौन में 487, बड़वानी में 56, अलीराजपुर में 23, खंडवा में 1999, धार में 9119, झाबुआ में 1872, इंदौर में 17298, मंदसौर 2077, नीमच 710, आगर-मालवा में 4353, देवास में 11215, रतलाम में 5684, शाजापुर में 14209, उज्जैन में 30215, अशोकनगर में 80, शिवपुरी में 222, ग्वालियर में 303, दतिया में 545, गुना में 366, भिंड में 137, श्योपुर में 367, मुरैना में 188, जबलपुर 42, बालाघाट 19, कटनी में 104, पांढुर्णा 2, डिंडोरी में 106, छिंदवाड़ा में 824, सिवनी में 1205, नरसिंहपुर में 1012, मंडला में 1696, हरदा में 1384, बैतूल में 1140, नर्मदापुरम में 6951, विदिशा में 7026, रायसेन में 9128, राजगढ़ में 8243, भोपाल में 6911, सीहोर में 31592, सतना में 309, रीवा में 328, सिंगरौली में 63, मऊगंज 5, मैहर में 36, सीधी में 393, अनूपपुर में 23, उमरिया में 359, शहडोल में 781, पन्ना में 345, निवाड़ी में 158, दमोह में 1018, टीकमगढ़ में 835, छतरपुर में 1280 और सागर में 3792 किसानों ने पंजीयन कराया है।


जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"


स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)